LOK SABHA

Wednesday, June 16, 1971/Jyaistha 26, 1893 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[Mr Speaker *in the Chair*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

भारत से काश्मीर को अलग करने के बारे में शेख अब्दुल्ला का कथित वक्तव्य

+

*511. श्री नाथू राम अहिरवार :
श्री चन्द्रिका प्रसाद :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारत से काश्मीर को अलग करने के उनके अपने निश्चय के बारे में शेख अब्दुल्ला द्वारा दिये गये उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जो 10 मई, 1971 के दैनिक "हिन्दुस्तान" में प्रकाशित हुआ था ; और

(ख) यदि हां तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस प्रकार की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) सरकार ने समाचार पत्रों में खबर देखी है।

(ख) सरकार प्रकाशित आशय को बिल्कुल गलत और विवेकहीन समझती है। देश की अखण्डता का आघात पहुंचाने की चेष्टा वाली किसी भी गतिविधि को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने आवश्यकता पड़ने पर कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की है और करेगी।

श्री चन्द्रिका प्रसाद : मुख्य न्यायाधीश जम्मू काश्मीर ट्राइब्यूनल ने पूरे प्लेबिसाइट फ्रंट को अवैधानिक कहा है और उसके सदस्यों के भाषण देने, घूमने फिरने आदि पर रोक लगाई है। अदालत की राय में शेख अब्दुल्ला और उनके साथ जो कर रहे हैं वह देशद्रोह का काम है। क्या भारत सरकार अदालत की राय के आधार पर कोई सख्त कार्रवाई करने का विचार कर रही है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : इससे ज्यादा सख्ती और क्या हो सकती है कि इस संस्था को अवैधानिक घोषित कर दिया गया ?

श्री चन्द्रिका प्रसाद : अदालत ने इस बात को माना है कि यह लोग देशद्रोह का काम कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार ने उनका भत्ता 1,000 रु० से बढ़ाकर 1,200 रु० कर दिया है, रहने की सुविधा भी दी है। क्या भारत सरकार इन सुविधाओं को छीनने का आदेश करेगी ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : भारत सरकार ने रुपया नहीं बढ़ाया। यह जम्मू और काश्मीर सरकार ने बढ़ाया और यह उनके अधिकार की चीज है। जहां तक रहने की सुविधा का प्रश्न है, उसको बढ़ाया नहीं गया है। जहां वह पहले रहते थे वहीं आज भी रहते हैं और उसका किराया भी देते हैं, बिजली पानी का खर्च भी देते हैं। किराया कंसेशनल रेट पर पर जरूर है।

SHRI S. A. SHAMIM : Is the Government aware of the statement that Shri Sheikh Abdulla made to the effect that India being mine motherland my primary interest would be to see that my as well as any one else's conduct does not adversely affect the honour of India. Shri Mirza Afzal Beg has also stated before the Tribunal that he does not support secession. In view of this, would the Government of India clarify its position with regard to Shiekh Abdulla and his other associates ?

SHRI K. C. PANT : In the Unlawful Activities Act the term "secession" has been defined in the following terms :

> "Secession of a part of the territory of India from the Union includes the assertion of any claim to determine whether such part will remain part of the territory of India."

In this context, any claim that the fact of accession of a part of the country is yet to be determined does come under the definition of the term "secession".

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या सरकार का ध्यान शेख अब्दुल्ला साहब के उस बयान की ओर गया है जिसमें उन्होंने पूर्वी बंगाल में पाकिस्तानी फौजों द्वारा किये जा रहे नरसंहार और अत्याचार की निन्दा करने से इन्कार किया है ? क्या यह भी सच है कि मुस्लिम मुशव्वरात की जिस बैठक में पूर्वी बंगाल में होने वाले अत्याचारों की निन्दा करने से इन्कार कर दिया गया था उसमें शेख साहब मौजूद थे ?

श्री कृष्ण चंद्र पन्त : यह प्रश्न इससे उठता तो नहीं है, लेकिन यह बात सही है कि शेख साहब उसमें थे । जो मुशव्वरात की सभा हुई उसमें उन्होंने शिरकत की । लेकिन उन्होंने कई बातें कही हैं । अखबारों में उनकी एक इन्टरव्यू की खबर भी आई है । हैदराबाद में जो इंटरव्यू उन्होंने दी थी उसमें कुछ बातें कही हैं जो हमें पसन्द नहीं हैं । लेकिन उसमें उन्होंने यह भी कहा है कि पूर्व बंगाल में पाकिस्तान ने ठीक रवैया अख्तियार नहीं किया । इस तरह से दोनों तरह की बातें उन्होंने इन्टरव्यू में कही हैं ।

श्री रामचन्द्र विकल : क्या गृह मंत्री जी का ध्यान इस समाचार की तरफ गया जिसमें काश्मीर गवर्नमेंट नें शेख अब्दुल्ला और उनके साथियों के ऊपर से पाबन्दी हटाने की बात कही है । यदि गया है तो सरकार इसके बारे में क्या सोच रही है ?

अध्यक्ष महोदय : आप इसमें ज्यादा चले गये । डेली हिन्दुस्तान में जो स्टेटमेंट छपा है उसके बारे में यह सवाल है ।

श्री रामचन्द्र विकल : यह स्टेटमेंट छपा है काश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से ।

श्री एस० ए० शमीम : ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है । वह बैन उठाना ही नही चाहते ।

श्री रामचन्द्र विकल : तो गवर्नमेंट कहे कि वह नहीं उठाना चाहती, या काश्मीर गवर्नमेंट ऐसा कहे । मेरी जानकारी यह है कि यह समाचार छपा है । गवर्नमेंट मना कर दे कि ऐसा समाचार हमने नहीं देखा ।

अध्यक्ष महोदय : डेली हिन्दुस्तान में जो निकला है उसका जवाब मन्त्री जी दे चुके है ।

श्री रामचन्द्र विकल : हिन्दुस्तान में यह समाचार भी छपा है जो मैं निवेदन कर रहा हूँ । काश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से छपा है ।

अध्यक्ष महोदय : सवाल में 10 मई के दिन जो लिखा है उसके बारे में पूछा गया है ।

SHRI TARUN GOGOI : May I know from the hon. Minister whether the alleged statement of Sheikh Abdullah, as it appeared in *Daily Hindustan*, violated any provision of the law ; if it did, why has no action been taken so far ?

SHRI K. C. PANT : It is not only a legal question but in these matters a final decision has to be taken about the action to be taken, when it is to be taken and the manner in which it has to be taken.